SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, we have certainly seen this somewhat alarmist report of one expert in the Conference in Berlin having predicted that prices could go to 182 dollars. Sir, people who predict petroleum prices, like those who read the palm, have the right to give us various views. But, we are very carefully monitoring it through several different sources, for example, Petroleum Economics Limited, Fesharaki Associate Consulting and Technology Services, etc. Our own IOC is tracking it through Platts and Argus and various journals and what is happening on the Petroleum exchanges, in particular, the International Petroleum Exchange and the New York Mercantile Exchange, and the forward curves are predicted by leading fund managers such as Morgan Stanley, Barclays, ABN Amro, Bank of America, Citibank and others. Sir, I would just give one example of why we think the figure of '182' is, probably, somewhat fanciful. We have here the prediction of Petroleum Economics Limited which says that in 2020-25, they do not expect Dated Brent to be very much higher than 62 dollars, of Western Texas Intermediate to be 64 dollars and 70 cents, and for the Japanese Crude Cocktail, which is, perhaps, a little bit more relevant to us because it is an Asian buyer, to be as low as 54.65. So, as far as we are concerned, when we look at the Asia-Pacific Databook, we find that with regard to 2020, Arab Light is predicted to be selling at as little as 40.85, not tomorrow or day afterwards, but out in 2020. ...(*Interruptions*) ... And then the low case price forecast for these is: Arab Light at 25 dollars 70 cents in 2020; Brent at 27 dollars 50 cents; and WTI at 29 dollars 75 cents. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: That is enough. ...(*Interruptions*)... That is enough. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kum Kum Rai.

*86. [The questioner (SHRIMATI KUM KUM RAI) was absent. For answer *vide* page 28 *infra*.]

हिमाचल प्रदेश में स्वां नदी का नहरीकरण

*87. श्री कृपाल परमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ऊना जिला में स्वां नदी के झालेड्रा पुल से संतोखगढ़ पुल तक 16.67 किलोमीटर लम्बे नहरीकरण के लिए 123.93 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 4 मार्च, 2002 को प्रेषित किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई तथा इस मामले को अभी तक लंबित रखने के क्या कारण हैं;.और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, यह प्रस्ताव जनवरी, 2002 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे बी आई सी) को आगे भेजे जाने के लिए इसे 4.3.2002 को आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया। जापान सरकार से उपलब्ध सीमित वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वित्त वर्ष 2002 के ऋण पैकेज के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, इसे वित्त वर्ष 2003 के लिए जापानी कार्यालयी विकास सहायता (ओडीए) के लिए प्रस्तुत किया था। स्वां नदी संबंधी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक अन्य परियोजना को कम प्राथमिकता दिए जाने, जो कि इस परियोजना की पूर्वापेक्षा थी, को ध्यान में रखते हुए जापान सरकार के वित्त वर्ष 2003 के ऋण पैकेज मे इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सका। राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जी बी आई सी को वित्त वर्ष 2004 के ऋण पैकेज के तहत विचार करने के लिए इस प्रस्ताव की दोबारा सिफारिश की। तथापि, जे बी आई सी ने इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई आई ए) में शामिल कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। हिमाचल प्रदेश सरकार से 2.12.2004 को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद, आर्थिक कार्य विभाग को स्थिति से अवगत कराया गया और इस परियोजना पर विचार करने के लिए इसे जे बी आई सी को भेजने का अनुरोध किया गया। इस परियोजना के लिए सहायता दिया जाना जापान सरकार से परियोजना का चयन करने संबंधी निर्णय पर निर्भर करता है।

Channellisation of Swan River in Himachal Pradesh

†*87. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Himachal Pradesh had on the 4th March, 2002 submitted a proposal of Rs.123.93 crores for 16.67 km. long Channellisation of river Swan in the Una district of Himachal Pradesh from Jhalera bridge to Santokhgarh bridge after its approval by Planning Commission and financial and administrative sanction by the Himachal Pradesh Government for providing financial assistance for the same;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, the details of action taken thereon and reasons for keeping the said matter pending till now; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir, the proposal was received in January 2002 itself.

(b) and (c) The proposal was processed and recommended to Department of Economic Affairs on 4.3.2002 for onward transmission to Japan Bank of International Cooperation (JBIC). In view of limited funding available from Government of Japan, the proposal could not be included in the list of projects posed for FY 2002 loan package. However, the same was posed for Japanese Official Development Assistance (ODA) for FY 2003. The proposal could not be included in the FY 2003 loan package of Government of Japan in view of low priority accorded to another project of Ministry of Environment & Forests on Swan River which was a pre-requisite to this project. In view of the request of the State Government, Government of India again recommended the proposal to JBIC for consideration under FY 2004 loan package. However, JBIC sought clarification on some of the issues included in the Environmental Impact Assessment (EIA) Report of the project. After receipt of the clarification from the Government of Himachal Pradesh on 2.12.2004, the Department of Economic Affairs has been informed of the position and requested to convey the same to JBIC for considering the project. The assistance for the project depends on the decision of the Government of Japan on selection of the project.

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 87 श्री कृपाल परमार।

श्री विक्रम वर्मा: सर, सप्लीमेंटरी?

श्री सभापति: सप्लीमेंटरी में क्वेश्चन्स आते नहीं हैं। माफ कीजिए, ज्यादातर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन वे मैंबर्स करते हैं जो कभी क्वेश्चन नहीं देते। मैं पहले यह भी देखूंगा कि आप क्वेश्चन देते हैं या नहीं देते अथवा केवल सप्लीमेंटरी पर ही डिपेंड करते हैं। श्री कृपाल परमार।

श्री कृपाल परमार: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा किसानों पर प्रकोप बरपाने वाली नदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और

उसमें कुल क्षेत्रफल की सात फीसदी कृषि योग्य भूमि है। स्वां नदी हर साल हजारों एकड़ भूमि बर्बाद करती है, जिसके लिए 1999 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस नदी के तटीयकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके लिए 106 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिसका काम चल रहा है। माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस नदी की 73 छोटी-बड़ी धाराएं हैं जिनका तटीयकरण किये बिना स्वां नदी के तटीयकरण का सपना अधूरा रहेगा। उसके लिए 2000 में एक परियोजना केन्द्र सरकार के माध्यम से जापान बैंक ऑफ इंटरनेशलन कोऑपरेशन को भेजी गयी थी। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ''स्वां नदी संबंधी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक अन्य परियोजना को कम प्राथमिकता दिए जाने, जो कि इस परियोजना की पूर्वापेक्षा थी, को ध्यान में रखते हुए जापान सरकार के वित्त वर्ष 2004 के ऋण पैकेज में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सका'' । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या वजह थी जिसके कारण 2003 में इस परियोजना को कम महत्व देकर इसको रोकने का काम किया? कृपया इस संबंध मे बताएं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, यह सही है कि यह योजना हिमाचल सरकार की तरफ से भारत सरकार के पास जनवरी, 2002 में पेश हुई। उस समय इस योजना के अंतर्गत दो धाराएं थीं-वाटरशेड मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट एंड लैंड डेवलपमेंट। तत्कालीन सरकार के पर्यावरण विभाग ने इस वाटरशेड मैनेजमेंट को कोई प्राथमिकता नहीं दी। इसके कारण, जापान सरकार की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ेशन्स ऋण देती हैं, उनको इसकी वायेबिलिटी के संबंध में कुछ शक पैदा हुआ। उन्होंने इसको भारत सरकार के पास वापस भेजा। वापस करने के बाद, सरकार जो environment impact assessment लेती है, तत्कालीन सरकार के environment impact assessment में यह कहा गया कि अगर इस प्रकार की योजना को मंजूरी दी जाएगी तो पंजाब के आनन्दपुर डाउनस्ट्रीम के सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार करने के समय यह सुझाव आया कि हिमाचल सरकार इसकी छानबीन करके वाटरशेड और फ्लड मैनेजमेंट को कंबाइन प्रोजेक्ट के रूप में पेश करे। हिमाचल सरकार ने कंबाइन प्रोजेक्ट के रूप में इसको दोबारा पेश किया। रिव्यू हो चुके हैं और 2 दिसम्बर, 2004, कुछ दिन पहले, इसको पेश भी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकानॉमिक अफेयर्स के द्वारा और माननीय मैम्बर को मैं आश्वस्त करता हूं कि आगामी मार्च के बाद हमारी सरकार की निगरानी में यह योजना हिमाचल को उपहारस्वरूप पेश की जाएगी।

Supply of gas to Andhra Pradesh

*88. SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Andhra Pradesh has approached his Ministry for restoration of full gas supplies to four independent power producers in the State;